www.railsamacharbureauald.com

सम्पूर्ण भारतीय रेल जगत का प्रथम पाक्षिक, प्रयागराज से प्रकाशित

रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

भारतीय रेलवेः एक ऐसा साथी जो आपकी गर्मी की छुट्टियों को यादगार सफर में बदल देता है

गर्मी की छुट्टियों में भारतीय रेलवे के साथ यात्रा, न सिर्फ मंजिल, बल्कि हर पल को खास बनाती है।

वर्ष-35 अंकः08 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 16-30 अप्रैल 2025 पृष्ठ 08 मूल्यः20 रु. मात्र + डाक खर्च (रंगीन सहित)

प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामेश्वरम में ₹8,300 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन।

रामेश्वरम के लिए नया पंबन ब्रिज प्रौद्योगिकी और परंपरा को एक साथ लाता हैः प्रधानमंत्री

सूत्र/रे.स.ब्यू- 06 अप्रैल 2025 को श्रीराम नवमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में ₹8,300 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर रामेश्वरम-तांबरम (चेन्नई) नई रेल सेवा और एक जहाज को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन कर कहा, "मैं आज खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे प्रार्थना का अवसर मिला।" उन्होंने कहा कि नया पंबन ब्रिज तकनीक और परंपरा का संगम है। यह 2.08 किमी लंबा पुल 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना है, जिसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर तक उठता है। प्रधानमंत्री ने कहा, "आज देश भर में मेगा प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।" उन्होंने बताया कि पिछले दशक में रेलवे, सड़क, बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे पर खर्च छह गुना बढ़ा है। तमिलनाडु में 4,000 किमी सड़कें, 77 रेलवे स्टेशन, और 11 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। इस पुल का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। रामायण के अनुसार, राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह पुल वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में खड़ा है। इसे 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसकी लंबाई 2.08 किमी है, इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठता है, जिससे जहाजों की सुचारू आवाजाही की सुविधा मिलती है और साथ ही निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित होता है। स्टेनलेस स्टील सुदृढीकरण, उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक पेंट और पूरी तरह से वेल्डेड जोड़ों के साथ निर्मित, पुल में अधिक स्थायित्व और कम रखरखाव की आवश्यकता है। इसे भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए दोहरी रेल पटरियों के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग इसे जंग से बचाती है, जिससे कठोर समुद्री वातावरण में दीर्घायु सुनिश्चित होती है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आर. एन. रवि, मंत्री अश्विनी वैष्णव और डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित थे।

"जानसू रेल टनल का ब्रेकथ्रू ऐतिहासिक" - केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

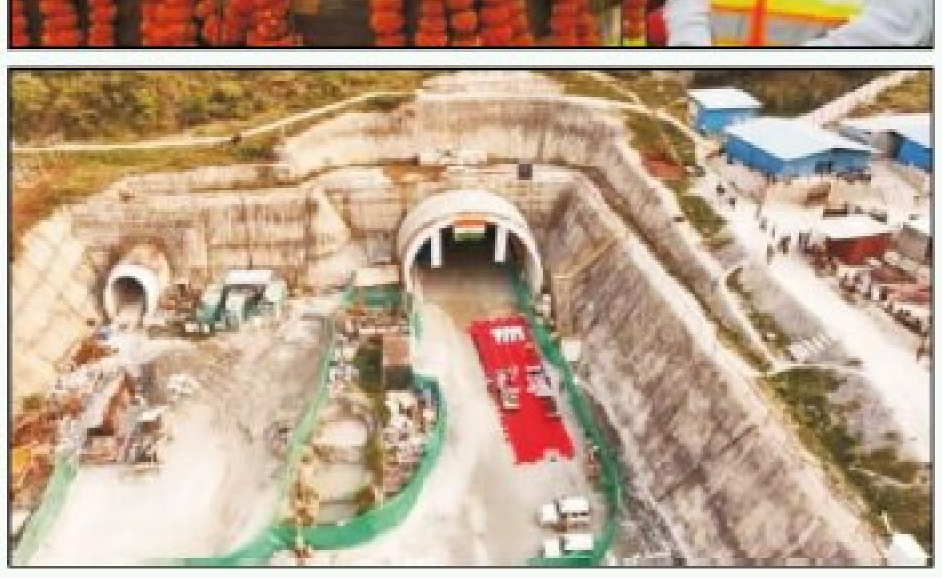

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय रेल मंत्री 16 अप्रैल, 2025 को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और उसके बाद देवप्रयाग और जनासू के बीच बन रही जनासू टनल का भी दौरा किया, जिसका बुधवार को ही ब्रेकथ्रू हुआ। इस दौरान उन्होंने रेलवे अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश भी दिए। देवप्रयाग और जनासू के बीच ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के अंतर्गत बन रही सबसे लंबी 14.57 किमी की टी-8 और टी-8एम डबल ट्यूब सुरंगों का ब्रेकथ्रू सफलता- पूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनासू रेलवे स्टेशन पहुंचकर सुरंग निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस मौके पर गढ़वाल सांसद श्री अनिल बलूनी और राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। 14.57 किलोमीटर लंबी इन सुरंगों का निर्माण अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) की मदद से किया गया है, जो परियोजना की तकनीकी दक्षता को दर्शाता है। वहीं, परियोजना की शेष सुरंगों का निर्माण पारंपरिक ड्रिल एंड ब्लास्ट तकनीक से किया जा रहा है। क्षेत्र की जटिल भूगर्भीय परिस्थितियों को देखते हुए सुरंगों की खुदाई के लिए विशेष टीबीएम मशीनें जर्मनी से मंगाई गई थीं। इसके अलावा जनासू से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक वर्टिकल शाफ्ट (कुआंनुमा सुरंग) भी बनाई गई है, जिससे खुदाई और निर्माण कार्य में सहायता मिल सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरंग निर्माण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की आधुनिक तकनीक से सुरंग निर्माण भविष्य की परियोजनाओं के लिए मिसाल बनेगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 अप्रैल, 2025 का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन, वर्ष 1853 में, भारत में पहली रेल बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी, और इस दिन ही भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल-जनासू टनल-का ब्रेकथ्रू भी हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल लाने का जो सपना था, वह अब साकार होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में यह सुरंग पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने सुरंग निर्माण में लगे सभी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और श्रमिकों को इस ब्रेकथ्रू के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इसे तकनीकी प्रगति, परिश्रम और सामूहिक प्रयासों का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह उपलब्धि आने वाले समय में प्रदेश के लिए विकास और कनेक्टिविटी के नए रास्ते खोलेगी।

भारतीय रेलवे, बेहतर अवसंरचना, बेहतर प्रौद्योगिकी, बेहतर रेलगाड़ियों के साथ मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में बेहतर सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है।

सूत्र/रे.स.ब्यू- मुंबई में आयोजित "बेहतर अवसंरचना, बेहतर प्रौद्योगिकी, बेहतर रेलगाड़ियां" विषय पर मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री वैष्णव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया और महाराष्ट्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर विशेष ध्यान देने के साथ आधुनिकीकरण, बेहतर यात्री अनुभव और बेहतर क्षेत्रीय संपर्क के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

बेहतर अवसंरचनाः

केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने इस बात पर बल दिया कि अवसंरचना का विकास उपनगरीय सेवाओं को बढ़ाने के लिए आधारशिला है। उन्होंने कहा कि लगभग 17,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएँ, 300 किलोमीटर से अधिक नई लाइनों को कवर करती हैं और वर्तमान में तीव्र गति से चल रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य मौजूदा लाइनों पर भीड़भाड़ कम करना, सेवा आवृत्ति में सुधार करना और मुंबई के उपनगरीय यात्रियों की लगातार बढ़ती माँग को पूरा करना है।

बेहतर प्रौद्योगिकीः

श्री वैष्णव ने कवच 5.0 के आगामी शुभारंभ की घोषणा की, जो उपनगरीय खंड के लिए तैयार की गई अत्याधुनिक सुरक्षा और सिग्नलिंग प्रणाली है। कवच 5.0 से अंतर-रेलगाडी हेडवे में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जिससे अधिक रेलगाडियां सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चल सकेंगी।

बेहतर रेलगाड़ियांः

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़े सुधार के अंतर्गत, जल्द ही 238 नए वातानुकूलित उपनगरीय रेक शुरू किए जाएंगे। इन रेकों को मुंबई के यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनोखे ढंग से डिजाइन किया गया है, जो अधिक आरामदायक और भरोसेमंद यात्रा का वादा करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस ने यह भी बताया कि मुंबई वन कार्ड जल्द ही शुरू किया जाएगा, जो उपनगरीय रेलगाड़ियों, मेट्रो रेल, मोनो-रेल, बेस्ट बसों आदि में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एमएमआर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को बदलने के लिए एकल और एकीकृत कार्ड है। इस बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और रोलिंग स्टॉक की उन्नति से उपनगरीय सेवाओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे लाखों मुंबई वालों के लिए दैनिक परिवहन में परिवर्तनकारी सुधार होगा। रचनात्मक क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई में स्थापित किया जाएगा और यह भारतीय रचनात्मक उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी कदम होगा, जिससे यह विश्व स्तरीय अवसंरचना केन्द्र बन जाएगा।

महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएँः

बातचीत के दौरान गोंदिया-बल्लारशाह रेलवे लाइन के दोहरीकरण की एक प्रमुख घोषणा थी, जो 4,819 करोड़ रुपये के निवेश से 240 किलोमीटर का महत्वपूर्ण गलियारा है। यह प्रमुख परियोजना विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ती है, जिससे भीड़भाड़ कम होगी और यात्री तथा माल ढुलाई में तेजी आएगी। यह आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र के रेल संपर्क को भी मजबूत करेगी, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इस प्रमुख बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने की घोषणा 7 अप्रैल, 2025 को की गई थी, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 18,658 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल लागत वाली रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी।

श्री वैष्णव ने कहा कि यह परिवर्तनकारी परियोजना उत्तर और दक्षिण भारत के बीच यात्री और माल ढुलाई संपर्क बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वीकृत परियोजना में 240 किलोमीटर लंबे मौजूदा रेल ट्रैक के साथ व्यापक उन्नयन शामिल है, जिसमें 29 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, 36 प्रमुख पुलों, 338 छोटे पुलों और 67 रोड अंडर-ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण शामिल है, ताकि परिचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके और सुरक्षा बढ़ाई जा सके। श्री वैष्णव ने कहा, ''इस दोहरीकरण से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संपर्क में काफी सुधार होगा। क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में तेजी से विकास होगा।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह यात्रियों और रेल लॉजिस्टिक्स पर निर्भर उद्योगों दोनों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस उन्नयन से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

अन्य उल्लेखनीय रेलवे परियोजनाओं में शामिल हैंः

इसके अलावा, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र में 132 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत देश भर में 1,300 स्टेशनों में से कई का काम पूरा होने वाला है, जबकि कई अन्य पर महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना मिली है।

भविष्य के लिए एक दृष्टिकोणः

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेलगाड़ी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बड़े पैमाने पर स्टेशन पुनर्विकास कार्यों के साथ-साथ ये महत्वाकांक्षी उपक्रम महाराष्ट्र में परिवहन में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। भारतीय रेलवे ने राज्य में अभूतपूर्व 1,73,804 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में महाराष्ट्र के रणनीतिक महत्व और इसके भविष्य के विकास पथ को रेखांकित करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस वर्ष मई के महीने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटन के मद्देनजर विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) की तैयारियों के महत्व को रेखांकित किया। श्री फडणवीस ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा महाराष्ट्र को रिकॉर्ड बजट आवंटन का महत्व और गोंदिया - बल्लारशाह स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण से क्षेत्र को लाभ हुआ। उन्होंने आईआरसीटीसी द्वारा जल्द ही छत्रपति शिवाजी महाराज और यशस्वी मराठा पर्यटन रेलगाड़ी चलाने की भी घोषणा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के अन्य सांस्कृतिक और तीर्थ स्थलों के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास और भव्य विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी द्वारा 10 दिनों की यात्रा के लिए एक विशेष रूप से तैयार की गई यात्रा की भी घोषणा की।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति-पाकला-कटपडी एकल रेलवे लाइन खण्ड (104 किमी) के दोहरीकरण को स्वीकृति दी, जिसकी कुल लागत 1332 करोड़ रुपये है

मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से करीब 400 गांवों और लगभग 14 लाख आबादी के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी

परियोजना निर्माण के दौरान लगभग 35 लाख मानव-दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित करेगी

सूत्र/रे.स.ब्यू- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति-पाकला-कटपडी एकल रेलवे लाइन खंड (104 किमी) के दोहरीकरण को स्वीकृति दे दी है, जिसकी कुल लागत लगभग 1332 करोड़ रुपये है। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास होगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नए भारत के विजन के अनुरूप है, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के जरिए क्षे‍त्र के लोगों को ''आत्मनिर्भर'' बनाएगा, जिससे उनके लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बेहतर होंगे। यह परियोजना मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के जरिए संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं तथा सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तीन जिलों को कवर करने वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 113 किलोमीटर तक बढ़ाएगी। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर तक कनेक्टिविटी के साथ-साथ परियोजना खंड अन्य प्रमुख स्थलों जैसे श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी फोर्ट आदि तक भी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जो देश भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना करीब 400 गांवों और लगभग 14 लाख आबादी के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। यह कोयला, कृषि वस्तुओं, सीमेंट और अन्य खनिजों आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए एक आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्य के परिणामस्वरूप 4 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है, जिससे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की लॉजिस्टिक्स लागत तथा तेल आयात (4 करोड़ लीटर) कम करने और कार्बन डाइयाक्साइड (CO2) उत्सर्जन (20 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद मिलेगी, जो एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने किया प्रयागराज-चोपन खंड का निरीक्षण।

सूत्र/रे.स.ब्यू- दिनांक 17 अप्रैल, 2025 को रेलवे संरक्षा आयुक्त, श्री प्रणजीव सक्सेना ने प्रयागराज चोपन खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान प्रयागराज मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) श्री नवीन प्रकाश, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर-I श्री शैलेश कुमार एवं अन्य अधिकारी एवं निरीक्षक उपस्थित थे। विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भारतीय रेल में एक विशेष निरीक्षण है, जिसमें चलती ट्रेन से निरीक्षण कार की पिछली खिड़की से ट्रैक और उसके आसपास के प्रतिष्ठानों जैसे सिग्नल, ओएचई, प्लेटफॉर्म आदि का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं और समग्र स्थिति, विशेष रूप से प्वाइंट और क्रॉसिंग पर ट्रेन की सवारी की गुणवत्ता, ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स (TGI) में सुधार की स्थिति, सिग्नल दृश्यता, सिग्नल बॉक्स की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर आदि रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा देखे गए। रेलवे सुरक्षा आयुक्त, श्री प्रणजीव सक्सेना रेलवे अधिकारियों के साथ प्रयागराज जंक्शन से विंध्याचल स्टेशन पहुंचे। रेलवे संरक्षा आयुक्त ने प्रयागराज मंडल के रेलवे अधिकारियों के साथ विंध्याचल स्टेशन एवं यार्ड का गहन निरीक्षण किया और बिंदुवार जानकारी ली। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने स्टेशन मास्टर कक्ष, रिले रूम, पॉइंट्स का विस्तृत निरीक्षण किया। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने विंध्याचल स्टेशन पर निरीक्षण के बाद सक्तेशगढ़ स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे संरक्षा आयुक्त ने प्रयागराज मंडल के रेलवे अधिकारियों के साथ सक्तेशगढ़ स्टेशन एवं यार्ड का विस्तृत निरीक्षण किया और बिंदुवार जानकारी ली। निरीक्षण के अगले क्रम में रेलवे सुरक्षा आयुक्त महोदय ने सक्तेशगढ़ सरसोंग्राम स्टेशनों के मध्य स्थित ब्रिज संख्या 46 का भी निरीक्षण किया। ब्रिज संख्या 46 के निरीक्षण के दौरान रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने सभी मानकों की बारीकी से जांच पड़ताल की और हवा के दबाव में ब्रिज की प्रतिक्रिया का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने चुनार चोपन खंड के घाट क्षेत्र का भी वृहद निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाट सेक्शन की कार्यप्रणाली एवं सुरक्षा मानकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और घाट सेक्शन में पड़ने वाले कर्व का भी निरीक्षण किया। इसी क्रम में उन्होंने सोन नदी पर बने रेलवे ब्रिज का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने कहा कि संरक्षा के लिए गुणवत्ता पूर्ण कार्य एवं मानकों का सख्ती से पालन किया जाए।

SCAN QR

Scan the Code for the Latest Verified
RAILWAYS NEWS ON OUR WEBSITE OR E-PAPER
हमारी वेबसाइट या ई-पेपर पर भारतीय रेलवे के सत्यापित समाचार को पढ़ने के लिए कोड को स्कैन करें
www.railsamacharbureauald.com

श्री रजनीश अग्रवाल ने ग्रहण किया मण्डल रेल प्रबन्धक/प्रयागराज का कार्यभार।

सूत्र/रे.स.ब्यू- दिनांक 03 अप्रैल 2025 को श्री रजनीश अग्रवाल ने उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मण्डल के मण्डल रेल प्रबन्धक (DRM) का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (भाड़ा विपणन) के पद पर कार्यरत थे। श्री अग्रवाल ने श्री हिमांशु बडोनी का स्थान लिया, जिनका स्थानांतरण उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक पद पर हुआ है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात श्री अग्रवाल ने संकल्प सभागार में शाखा अधिकारियों संग बैठक की, जिसमें श्री बडोनी भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री अग्रवाल ने कहा, ''संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। टीम भावना से कार्य करते हुए हमें प्रयागराज मंडल को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।'' श्री रजनीश अग्रवाल 1997 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के अधिकारी हैं। उन्होंने 1993 में आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और 1998 में रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा से प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय रेलवे में सेवाएं आरंभ कीं। अपने करियर में उन्होंने पश्चिम रेलवे में क्षेत्रीय प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, उप मुख्य परिचालन प्रबंधक, मुख्य यातायात प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे इस्पात, सीमेंट, कोयला, खाद्यान्न और कंटेनर संचालन जैसे उद्योगों से निकटता से जुड़े रहे हैं तथा रेलवे की माल ढुलाई वृद्धि में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारतीय रेलवे में प्रणाली सुधार, पारदर्शिता एवं लॉजिस्टिक्स लागत में कमी हेतु उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है।

उत्तर मध्य रेलवे ने 272.22 करोड़ रुपये का स्क्रैप बेचकर राजस्व अर्जित किया।

सूत्र/रे.स.ब्यू- उत्तर मध्य रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्क्रैप निष्पादन के ₹260.00 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹272.22 करोड़ का सकल राजस्व अर्जित किया है। उत्तर मध्य रेलवे के उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में उप मुख्य सामग्री प्रबंधक / प्रणाली एवं झाँसी वर्कशॉप द्वारा ₹145.13 करोड़ की बिक्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री उपेन्द्र चन्द जोशी के मार्गदर्शन एवं प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक श्री एस. पी. द्विवेदी के नेतृत्व में डिपो एवं डिवीजनों ने मिलकर विभिन्न प्रकार के स्क्रैप जैसे कि कंडेम्न्ड वैगन, कोच, पानी की टंकियों, स्टील स्ट्रक्चर्स, नॉन-फेरस इत्यादि का निष्पादन किया। उत्तर मध्य रेलवे सदैव स्क्रैप निष्पादन को प्राथमिकता देता रहा है और इसकी सावधिक समीक्षा उच्च स्तर पर होती रही है। इससे न केवल राजस्व का अर्जन हुआ है, बल्कि परिसर को स्वच्छ रखने में मदद मिली एवं बहुमूल्य रेलवे भूमि भी रेलवे के उपयोग हेतु खाली हुई है। उत्तर मध्य रेलवे 'जीरो स्क्रैप' का लक्ष्य हासिल करते हुए अपने परिसरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यूटीएस ऑन मोबाइल टिकटिंग से मार्च माह में 1 लाख 22 हजार से अधिक रेल टिकट बुक।

सूत्र/पमरे- रेलवे में यात्रियों की सुविधा हेतु यूटीएस मोबाइल ऐप से ऑनलाइन अनारक्षित टिकट बनाई जा रही है। इसके लिए प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के निर्देशन में पश्चिम मध्य रेल में तीनों मंडलों के वाणिज्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप माह मार्च 2025 में यूटीएस ऐप से बुक कुल 1,22,685 टिकटों से 6,56,515 यात्रियों ने यात्रा की, जिससे रेलवे को 1 करोड़ 31 लाख 03 हजार 575 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। पश्चिम मध्य रेल के सभी स्टेशनों पर ऑनलाइन जनरल टिकट के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा दी जा रही है। यात्रियों के बीच इस ऐप की लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ अनारक्षित टिकट लेने के आंकड़ों में भी काफी वृद्धि हुई है। इस ऐप के माध्यम से माह मार्च 2025 में मंडलवार जानकारी इस प्रकार है:

- जबलपुर मंडलः यूटीएस मोबाइल ऐप के द्वारा कुल 35,170 बुक टिकटों से 2,93,702 यात्रियों ने यात्रा की, जिससे रेलवे को 43 लाख 37 हजार 690 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- भोपाल मंडलः यूटीएस मोबाइल ऐप के द्वारा कुल 40,033 बुक टिकटों से 2,06,607 यात्रियों ने यात्रा की, जिससे रेलवे को 46 लाख 27 हजार 255 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- कोटा मंडलः यूटीएस मोबाइल ऐप के द्वारा कुल 47,400 बुक टिकटों से 1,55,852 यात्रियों ने यात्रा की, जिससे रेलवे को 41 लाख 32 हजार 630 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

रेलवे ने ऐप से टिकट बुक करने संबंधित अधिक जानकारी वेबसाइट **www.utsonmobile.indianrail.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है। रेल प्रशासन ने अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील की है कि वे मोबाइल टिकटिंग ऐप पर यूटीएस के उपयोग को बढ़ावा दें और उपयोग से जुड़े हितों का लाभ उठाएं।

भारत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,681 लोकोमोटिव का उत्पादन करके अमेरिका और यूरोप से आगे निकला

सूत्र/रे.स.ब्यू- वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे ने 1,681 लोकोमोटिव का रिकॉर्ड उत्पादन कर लोकोमोटिव निर्माण में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया है। यह संख्या अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त उत्पादन से अधिक है, जो भारत के वैश्विक रेलवे क्षेत्र में बढ़ते वर्चस्व को दर्शाता है। भारतीय रेलवे की निर्माण इकाइयों ने पिछले वर्ष के 1,472 लोकोमोटिव की तुलना में 209 अधिक लोकोमोटिव बनाए, जो 19% वृद्धि और अब तक का सबसे ऊंचा वार्षिक उत्पादन है। यह सफलता "मेक इन इंडिया" पहल के तहत लिए गए रणनीतिक निर्णयों का परिणाम है। जहाँ 2004 से 2014 के बीच भारत ने कुल 4,695 लोकोमोटिव बनाए (औसतन 470 प्रति वर्ष), वहीं 2014 से 2024 के बीच यह संख्या बढ़कर 9,168 हो गई (औसतन 917 प्रति वर्ष)। यह भारत की निर्माण क्षमता में दोगुनी से अधिक वृद्धि को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न इकाइयों का योगदान इस प्रकार रहा:

- चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW): 700
- बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW): 477
- पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW): 304

मधेपुरा और मढ़ौरा इकाइयाँ: 100-100 उत्पादित लोकोमोटिवों में से अधिकांश माल ढुलाई के लिए हैं।

श्रेणियों का वितरण:

- WAG-9/9H: 1,047
- WAG-9HH: 7
- WAG-9 ट्विन: 148
- WAP-5: 2
- WAP-7: 272
- NRC: 5
- WAG-12B: 100
- WDG 4G/6G: 100

यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाई को दर्शाती है।

मथुरा-गंगापुर सिटी-मथुरा के मध्य स्पेशल ट्रेन का संचालन।

सूत्र/रे.स.ब्यू- यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मथुरा-गंगापुर सिटी-मथुरा के मध्य स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर रेल प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। गाड़ी संख्या 04191/04192 मथुरा-गंगापुर सिटी-मथुरा स्पेशल ट्रेन दिनांक 01 अप्रैल से 30 जून 2025 तक दोनों दिशाओं में कुल 91-91 ट्रिप चलेगी। इस गाड़ी में कुल 12 कोच होंगे। गाड़ी संख्या 04191 मथुरा-गंगापुर सिटी स्पेशल मथुरा से शाम 16:15 बजे प्रस्थान कर मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकते हुए रात 22:55 बजे गंगापुर सिटी पहुँचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 04192 गंगापुर सिटी-मथुरा रात 23:25 बजे गंगापुर सिटी से प्रस्थान कर मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 07:00 बजे मथुरा पहुँचेगी। गाड़ी के हाल्टः यह गाड़ी दोनों दिशाओं में मथुरा से गंगापुर सिटी के मध्य गोवर्धन, डीग, बांज नगर, गोविंदगढ़, रामगढ़, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई जंक्शन, दौसा जंक्शन, नांगल राजावतान, लालसोट, मंडावरी, पिपलाई एवं बामनवास स्टेशनों पर रुकेगी। रेल यात्रियों से अनुरोध है कि स्पेशल ट्रेन की विस्तृत जानकारी रेलवे स्टेशन, रेल मदद 139 एवं एनटीईएस ऑनलाइन से प्राप्त करें।

महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे द्वारा मथुरा जंक्शन स्टेशन की विभिन्न रेलवे सुविधाओं का निरीक्षण

सूत्र/रे.स.ब्यू- दिनांक 11.04.2025 को महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, श्री उपेन्द्र चन्द्र जोशी ने मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। तृतीय प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया उसके उपरांत प्लेटफॉर्म संख्या 01 के निरीक्षण के दौरान बेहतर साफ-सफाई, यात्री सुविधाओ पर जोर दिया,मथुरा जंक्शन स्टेशन के वीआईपी लाउंज में मंडल रेल प्रबंधक श्री तेज प्रकाश अग्रवाल व संबंधित अधिकारियों के साथ पुनर्विकास कार्यों से संबंधित लेआउट प्लान का अवलोकन किया एवं स्टेशन पुनर्विकास पर गहन चर्चा की। स्टेशन के समुचित विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने द्वितीय प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया व यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए विस्तृत योजना पर चर्चा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रेलवे सेवाओं को और अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित किया। महाप्रबंधक महोदय ने स्टेशन के निरीक्षण के दौरान मीडिया को भी सम्बोधित किया और बताया कि मथुरा जंक्शन स्टेशन का पुनर्विकास कार्य होना है जिसमें स्टेशन पर नव-निर्मित फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म तथा स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके उपरांत महाप्रबंधक महोदय ने मथुरा जंक्शन पर कार्यरत कुलियों के साथ भेंटवार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और उनके सुझावों को सुना। मथुरा जंक्शन के निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक के साथ मंडल रेल प्रबंधक श्री तेज प्रकाश अग्रवाल व मंडल के शाखा अधिकारी, निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार - 2025

अपने सफर की कहानी लिखें और इनाम पाएं।

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेल आपके सफर की अनकही कहानियों को मंच देने जा रही है! यदि आपके पास रेल यात्रा का कोई यादगार अनुभव है, जिसे शब्दों में पिरोकर दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं, तो रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना 2025 आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस प्रतियोगिता में भाग लें और आकर्षक नकद पुरस्कार जीतें! रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में हिंदी में मौलिक और रोचक यात्र वृत्तांत लिखने वाले प्रतिभागियों को ₹10,000 (प्रथम पुरस्कार), ₹8,000 (द्वितीय पुरस्कार), ₹6,000 (तृतीय पुरस्कार) और पाँच प्रेरणा पुरस्कार (प्रत्येक ₹4,000) दिए जाएंगे। आपकी कहानी 3000 से 3500 शब्दों के बीच होनी चाहिए, जिसे डबल स्पेस में टाइप किया गया हो और प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम संख्या अंकित हो। कुल शब्दों की संख्या भी स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। साथ ही, अपने वृत्तांत के साथ एक अलग पृष्ठ पर अपना नाम, पदनाम, आयु, पता, मात भाषा, मोबाइल नंबर और ई-मेल जरूर भेजें। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, तो आपको प्रमाणित करना होगा कि आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है। अन्य प्रतिभागियों को यह पुष्टि करनी होगी कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है। साथ ही, सभी प्रतिभागियों को यह घोषणा करनी होगी कि उनकी रचना मौलिक है और इसे पहले किसी अन्य प्रतियोगिता में पुरस्कृत नहीं किया गया है। अपने शब्दों से अपनी रेल यात्रा के जादू को जीवंत करें और अपने लेखन से दें उसे नया आकार! अपनी प्रविष्टि दो प्रतियों में 31 जुलाई, 2025 तक दिए गए पते पर भेजें: **सहायक निदेशक, हिंदी (प्रशिक्षण), कमरा नंबर 316, कॉफमो रेल कार्यालय परिसर, तिलक ब्रिज, आईटीओ, नई दिल्ली 110002**

श्री तुषार कान्त पाण्डेय ने पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार 09 अप्रैल, 2025 को ग्रहण कर लिया।

सूत्र/रे.स.ब्यू- श्री तुषार कान्त पाण्डेय ने पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार 09 अप्रैल, 2025 को ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व, आप पूर्व तटीय रेलवे में सम्बलपुर मंडल तथा मध्य रेलवे में नागपुर मंडल के मंडल रेल प्रबन्धक के पद पर कार्यरत थे। श्री तुषार कान्त पाण्डेय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक (बी.टेक.), आई.आई.टी., दिल्ली से परास्नातक (एम.टेक.) तथा एफ.एम.एस. विश्वविद्यालय, दिल्ली से एम.बी.ए. की उपाधि प्राप्त की। श्री पाण्डेय ने भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा (आई.आर.एस.ई.) के बैच-1992 के माध्यम से रेल सेवा में पदार्पण किया। आपने सहायक मंडल इंजीनियर, फतेहपुर तथा विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय), उप मुख्य इंजीनियर एवं मुख्य इंजीनियर के पदों पर कार्य किया। आपने रेलवे बोर्ड तथा अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) में निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों का निर्वहन किया। आपको विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और रेलवे बोर्ड में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए रेलवे प्रणालियों के सभी क्षेत्रों का व्यापक एवं समृद्ध अनुभव है। श्री पाण्डेय ने आइक्लिफ/मलेशिया, इनसीड/सिंगापुर एवं आई.एस.बी./हैदराबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपने एरौमा/शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) में भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व किया है। निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक ट्रैक व ट्रैक मशीन, रेलवे बोर्ड के कार्यकाल में आपने ऑस्ट्रिया व चेक गणराज्य में प्रतिष्ठित संस्थानों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपको रेल प्रबन्धन एवं प्रशासन का गहन अनुभव प्राप्त है। आप रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों में समान रूप से लोकप्रिय हैं।

140 वर्ष पुराने ब्रिज को किया प्रतिस्थापित, महज 6 घंटे में पूरा हुआ कार्य।

सूत्र/रे.स.ब्यू- झांसी रेल मंडल द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। दिनांक 17.04.2025 को मंडल द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य किया गया। मंडल द्वारा झांसी कानपुर खंड के पारीछा चिरगांव अप लाइन पर स्थित 140 साल पुराने ब्रिज को प्रतिस्थापित किया गया। यहाँ स्टोन स्लैब ब्रिज की जगह 2.0×2.1 मीटर के आरसीसी बॉक्स लगाए गए। यह कार्य महज 6 घंटे में पूरा कर लिया गया। पारीछा चिरगांव अप लाइन पर वर्ष 1885 में ब्रिज संख्या 1157/1 का निर्माण किया गया था। पुराने ब्रिज के निर्माण में ईंट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इसका आकार 2.0×0.61 मीटर था। 140 वर्ष बाद ईंट और पत्थर के स्थान पर 2.0×2.1 मीटर के आरसीसी बॉक्स को प्रतिस्थापित किया गया है। आरसीसी बॉक्स की स्थापना के बाद यह ब्रिज 25 टन तक का भार उठाने में सक्षम हो गया है। यह ब्रिज झांसी कानपुर खंड के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अहम भूमिका निभाएगा। मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक कुमार सिन्हा ने कहा कि मंडल के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सतत रूप से जारी है। 140 वर्ष पुराने ब्रिज को नई मजबूती प्रदान की गई है। इससे ट्रेन का आवागमन और समयपालनता बेहतर होगी।

अमृत स्टेशन योजना के अन्तर्गत राजगढ़ स्टेशन पर पुनर्विकास का कार्य पूर्ण होने की ओर अग्रसर।

सूत्र/रे.स.ब्यू- उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में स्थित राजगढ़ स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 13.10 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास कार्य अंतिम चरण में है। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देना और यात्री सुविधाओं को बढ़ाना है। राजगढ़ स्टेशन सहित 77 स्टेशनों का लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पहले पुराने भवन में स्थान की कमी के कारण सुविधाओं का विस्तार संभव नहीं था, लेकिन अब नया स्टेशन भवन विस्तृत टिकटिंग क्षेत्र, बड़ा वेटिंग हॉल और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान के लिए सुव्यवस्थित सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग स्पेस में सुधार, प्लेटफॉर्म शेल्टर, स्वच्छ शौचालय, पानी बूथ, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं और 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। इस पुल को सिर्फ 4 घंटे 25 मिनट के ट्रैफिक ब्लॉक में तैयार किया गया, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। राजगढ़ स्टेशन का पुनर्विकास स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के साथ आधुनिक तकनीक का समावेश करता है। यह स्टेशन क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। जयपुर मंडल के अंतर्गत राजगढ़ सहित 18 स्टेशनों का 1325 करोड़ रुपये से पुनर्विकास हो रहा है, जिसमें जयपुर, अलवर, दौसा, फुलेरा, सीकर जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष की तुलना में सभी वस्तुओं में 1.68% की वृद्धिशील लोडिंग दर्ज की, घरेलू कंटेनर की लोडिंग में 19.72% की मजबूत वृद्धि।

सूत्र/रे.स.ब्यू- गनी बोरी, हॉट रोल्ड कॉइल, सिरेमिक टाइलें, वॉल केयर पुट्टी और चावल, घरेलू कंटेनर में लोडिंग की जाने वाली पांच प्रमुख वस्तुएं हैं। घरेलू कोयले की लोडिंग 7-4: और उर्वरक 1.2: तक बढ़ी। भारतीय रेलवे थोक वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, जो उद्योग और ऊर्जा के लिए आवश्यक हैं - बिजली संयंत्रों के लिए कोयला, विनिर्माण और निर्माण के लिए लौह अयस्क और तैयार स्टील, सीमेंट, राष्ट्रीय वितरण के लिए खाद्यान्न, कृषि के लिए उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पाद। लंबी दूरी और थोक वस्तुओं के लिए, रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में अधिक किफायती रहा है। यह व्यवसायों के लिए समग्र रसद लागत को कम करने में मदद करता है, जिससे भारतीय सामान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। इसके अलावा, रेलवे देश भर में खानों, कारखानों, कृषि क्षेत्रों और बंदरगाहों को बाजारों से जोड़ता है, जिससे निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सक्षम होती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय रेलवे ने लगभग 1617.38 मीट्रिक टन प्रारंभिक माल ढुलाई हासिल की, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1590.68 मीट्रिक टन की तुलना में, 26.70 मीट्रिक टन (1.68%) की वृद्धिशील लोडिंग दर्ज की। घरेलू कोयले के लिए लोडिंग में 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि घरेलू कंटेनर के लिए लोडिंग में 19.72% की वृद्धि दर्ज की गई। उर्वरक के लिए लोडिंग में 1.25% की वृद्धि दर्ज की गई। पीओएल लोडिंग ने 0.61% की वृद्धि दर्ज की। गनी बोरी, हॉट रोल्ड कॉइल, सिरेमिक टाइलें, वॉल केयर पुट्टी और चावल घरेलू कंटेनर में पांच प्रमुख वस्तुएं हैं। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा प्राप्त लोडिंग के संदर्भ में, पूर्व रेलवे ने 16.11 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) ने 7.28% की वृद्धि हासिल की। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 4.21% की वृद्धि हासिल की। उत्तर रेलवे ने 3.89% की वृद्धि हासिल की। पूर्व मध्य रेलवे ने 2.82 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। दक्षिण मध्य रेलवे ने 2.14% की वृद्धि हासिल की। पूर्व तटीय रेलवे ने 1.19% की वृद्धि हासिल की। दक्षिण रेलवे ने 0.80% की वृद्धि हासिल की। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 0.36% की वृद्धि हासिल की। भारतीय रेलवे द्वारा कोयले की प्रभावशाली लोडिंग के कारण, भारत में पावर हाउसों का स्टॉक 57 मीट्रिक टन तक पहुंचाया गया।

भारतीय रेलवे ने पारदर्शी राजस्व निगरानी के लिए डिजिटल समाधानों को लागू किया

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे ने प्रत्येक स्टेशन पर प्राप्त राजस्व की निगरानी के लिए एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली विकसित की है। स्टेशनों को यात्री आय और ट्रैफिक के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे एनएसजी, एसजी और एचजी। राजस्व के प्रमुख स्रोतों में आरक्षित और अनारक्षित यात्री टिकट, माल ढुलाई, पार्सल, प्लेटफॉर्म टिकट, खानपान, विज्ञापन और भूमि पट्टे से होने वाली आय शामिल है। राजस्व की निगरानी स्टेशन, खंड और मंडल स्तरों पर नामित अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने कई डिजिटल समाधान लागू किए हैं, जो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) द्वारा विकसित किए गए हैं। प्रमुख डिजिटल सिस्टम में यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS), माल संचालन सूचना प्रणाली (FOIS), पार्सल प्रबंधन प्रणाली (PMS), यातायात खाता प्रबंधन प्रणाली (TAMS), ऑनलाइन भुगतान और ई-बैलेंस शीट जैसे उपकरण शामिल हैं। इन समाधानों ने पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता में सुधार किया है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे अपने मानव संसाधनों के कुशल और तर्कसंगत उपयोग पर भी ध्यान दे रहा है। कर्मचारियों के कार्यभार का मूल्यांकन समय-समय पर कार्य अध्ययन और मानकीकरण के माध्यम से किया जाता है। कार्य घनत्व, नई तकनीकों और परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बदलाव किए जाते हैं। एचओईआर (HOER) जैसे नियमों के तहत कर्मचारियों की ड्यूटी और वर्गीकरण का भी विश्लेषण होता है। इससे रेलवे को नई परियोजनाओं में जनशक्ति के समुचित उपयोग में मदद मिलती है।

पाठकों से अनुरोध

आपको यह अंक कैसा लगा ?
इसमें आप और क्या परिवर्तन चाहते हैं ?
कृपया अपने सुझावों से अवश्य ही अवगत कराएं जिससे हम पत्रिका में सुधार कर सकें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा।

प्रधान संपादक

कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी

सूत्र/रे.स.ब्यू- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए (लगभग) है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली ये चार परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1247 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।

इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

- संबलपुर-जरापदा तीसरी और चौथी लाइन
- झारसुगुड़ा-सासोन तीसरी और चौथी लाइन
- खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा 5वीं और 6वीं लाइन
- गोंदिया-बल्हारशाह दोहरीकरण

इस वर्धित लाइन क्षमता से गतिशीलता में सुधार होगा जिससे भारतीय रेलवे के लिए बेहतर दक्षता और सेवा विश्वसनीयता प्राप्त होगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएंगे और भीड़भाड़ को कम करेंगे जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास होगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से लोगों को ''आत्मनिर्भर'' बनाएगा, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हो पाई हैं और लोगों की आवाजाही और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। इन परियोजनाओं के साथ 19 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा जिससे दो आकांक्षी जिलों (गढ़चिरौली और राजनांदगांव) में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3350 गांवों और लगभग 47.25 लाख आबादी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा मार्ग से बलौदा बाजार जैसे नए क्षेत्रों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी जिससे क्षेत्र में सीमेंट संयंत्रों सहित नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की संभावनाएं बनेंगी। ये कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 88.77 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन साधन होने के नाते रेलवे, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (95 करोड़ लीटर) को कम करने और CO2 उत्सर्जन (477 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा जो 19 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

पूर्व मध्य रेल द्वारा माल ढुलाई में ऐतिहासिक उपलब्धि-200 मिलियन टन माल ढुलाई वाले क्लब में शामिल होने का गौरव हासिल।

सूत्र/रे.स.ब्यू- पूर्व मध्य रेल द्वारा 2024-25 में माल ढुलाई में 200 मिलियन टन तथा प्रारंभिक आय में 30 हजार करोड़ रुपये प्रारंभिक राजस्व प्राप्त करने वाले क्लब में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ है। महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह ने पूर्व मध्य रेल की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। वर्ष 2024-25 में पूर्व मध्य रेल की कुल प्रारंभिक आय 31,303 करोड़ रुपये रही, जो अब तक का रिकॉर्ड है। माल ढुलाई के क्षेत्र में रिकॉर्ड कायम करते हुए 2024-25 में 200.32 मिलियन टन माल ढुलाई कर, पूर्व मध्य रेल भारतीय रेल के 04 प्रथम क्षेत्रीय रेलों में शामिल होने का गौरव हासिल किया गया है। माल ढुलाई से 26,106 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जिससे पूर्व मध्य रेल भारतीय रेलवे में दूसरा सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला क्षेत्रीय रेल बना। इसी तरह, यात्री यातायात से प्राप्त रेल राजस्व के क्षेत्र में पूर्व मध्य रेल ने भारतीय रेलवे में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2024-25 में 4,580 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त किया। यह राजस्व पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 4,088 करोड़ रुपये की तुलना में 12.01 प्रतिशत अधिक है।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित स्टार्टअप ने भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक लॉन्च किया

सूत्र/रे.स.ब्यू- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा समन्वित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित आठ स्टार्टअप्स में से एक, बेंगलुरु स्थित क्यूपीआईएआई ने कल विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर 25 सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स क्षमता वाले भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक को लॉन्च करने की घोषणा की। क्यूपीआईए-आई-इंडस, क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है और ये देश का पहला फुल-स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसमें उन्नत क्वांटम हार्डवेयर, स्केलेबल कंट्रोल और ट्रांसफॉर्मेटिव हाइब्रिड कंप्यूटिंग के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर का संयोजन किया गया है। यह उन्नत क्वांटम प्रोसेसर, अगली पीढ़ी के क्वांटम-एचपीसी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और एआई-एन्हांस्ड क्वांटम समाधानों को एकीकृत करता है। क्यूपीआईएआई जीवन विज्ञान, औषधि खोज, सामग्री विज्ञान, गतिशीलता, रसद, स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में गहन विज्ञान और गहन तकनीक नवाचार को आगे बढ़ा रहा है। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के एक हिस्से के रूप में, क्यूपीआईएआई देश के क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी इको-सिस्टम, राष्ट्रीय क्वांटम अपनाने के कार्यक्रमों और दुनिया के सबसे बड़े क्वांटम प्रतिभा इको-सिस्टम में से एक बनाने में सबसे आगे है। क्यूपीआईएआई भारत की क्वांटम यात्रा को गति देने, क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकों को व्यावहारिक, सुलभ और वैश्विक रूप से प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2019 में बूटस्ट्रैप की गई कंपनी की तकनीकों ने 11 पेटेंट आवेदनों की उपलब्धि और प्रति वर्ष लगभग 1 मिलियन रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। उन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से भी पर्याप्त पूंजी जुटाई है। विश्व क्वांटम दिवस उद्योगों को बदलने, वैज्ञानिक खोज को गति देने और नवप्रवर्तकों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने वाले क्वांटम-सक्षम भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण को चिह्नित करता है। इस घोषणा के साथ क्यूपीआईएआई क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त उल्लेखनीय प्रगति और संभावनाओं को तलाशने की मुहिम में लगे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और उत्साही लोगों के वैश्विक समुदाय में शामिल हो गया है।

उत्तर पूर्वी राज्यों की सैर कराने 22 अप्रैल को रवाना की जाएगी भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन।

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेल, देश के पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन को बढ़ाने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन का संचालन शुरू कर रही है। इस ट्रेन को 22 अप्रैल 2025 को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया जाना प्रस्तावित किया गया है। कुल 15 दिनों की इस यात्रा में पर्यटकों को असम स्थित गुवाहाटी, काजीरंगा, जोरहाट व शिवसागर, अरुणाचल प्रदेश में इटानगर, नागालैंड में दिमापुर व कोहिमा, त्रिपुरा में उनाकोटी, अगरतला व उदयपुर तथा मेघालय स्थित शिलॉन्ग व चेरापूंजी का भ्रमण कराया जाएगा। आधुनिक साज-सज्जा के साथ तैयार डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन द्वारा पर्यटकों को न केवल पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का भी मौका प्राप्त होगा। भारत गौरव ट्रेन द्वारा संचालित यह यात्रा पूर्वोत्तर के राज्यों को रेल के द्वारा देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी और घरेलू पर्यटकों को पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए प्रेरित करेगी। दिल्ली से रवाना होकर पर्यटक ट्रेन गुवाहाटी पहुंचेगी, जहां कामाख्या देवी मंदिर व उमानंद मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। होटलों में रात्रि विश्राम होगा। साथ ही पर्यटक गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज का आनंद भी ले सकेंगे। गुवाहाटी से चलकर यह ट्रेन अरुणाचल स्थित नाहरलगुन स्टेशन के लिए रवाना होगी, जहां पर्यटकों को प्रदेश की राजधानी इटानगर स्थित गोम्पा बौद्धिस्ट मंदिर और थेरवाद बौद्धिस्ट मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। ट्रेन का अगला पड़ाव असम के पूर्वी भाग में स्थित शिवसागर होगा, जो प्राचीन अहोम वंश की राजधानी रहा है। शिवसागर में प्राचीन शिव मंदिर व अन्य विरासत स्थलों का भ्रमण करने के उपरांत पर्यटक जोरहाट के चाय बागान देखते हुए काजीरंगा के लिए बसों द्वारा रवाना किए जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम भी होगा और अगले दिन पर्यटकों को काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य का भ्रमण कराया जाएगा। काजीरंगा से चलकर पर्यटक फुरकटिंग रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां से ट्रेन पर सवार होकर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए रवाना होंगे। त्रिपुरा में पर्यटक दो दिनों के अंदर उनाकोटी के विरासत स्थल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों जैसे उजयंता महल व नीर महल का भ्रमण करेंगे। साथ ही पर्यटकों को उदयपुर स्थित शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर का दर्शन भी कराया जाएगा। यहाँ से ट्रेन अपने अगले पड़ाव नागालैंड स्थित दिमापुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी। इस यात्रा में बदरपुर से लेकर लूमडिंग रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ट्रेन यात्रा के माध्यम से लिया जा सकेगा। दिमापुर से पर्यटक बसों द्वारा नागालैंड की राजधानी कोहिमा जाएंगे, जहां कोहिमा शहर के दर्शनीय स्थानों के भ्रमण के साथ ही पर्यटकों को स्थानीय नागा समुदाय की जीवन शैली को देखने के लिए खोनोमा गाँव का भ्रमण के साथ ही कोहिमा में रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी कराई जाएगी। दिमापुर से ट्रेन अगले दिन गुवाहाटी के लिए प्रस्थान करेगी। गुवाहाटी पहुँचकर पर्यटकों को बसों द्वारा मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग ले जाया जाएगा, जहां पर्यटक प्रसिद्ध ऊमियम झील व अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगे। शिलॉन्ग में रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन पर्यटक बसों द्वारा चेरापूंजी के आकर्षक प्राकृतिक स्थलों, सुंदर झरनों व प्राचीन गुफाओं को देखेंगे और शाम को गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएंगे। गुवाहाटी से रात्रिकाल में ट्रेन पर्यटकों को लेकर दिल्ली वापसी के लिए प्रस्थान करेगी व यात्रा के 15वें दिन दिल्ली पहुंच जाएगी। इस दौरान ट्रेन द्वारा लगभग 5800 किमी की यात्रा पूरी की जाएगी।

यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था

यात्रा के दौरान एसी प्रथम, एसी द्वितीय पर्यटकों को ट्रेन की पैंट्री में निर्मित शुद्ध शाकाहारी भोजन ट्रेन के रेस्टोरेंट में परोसा जाएगा। एसी तृतीय श्रेणी के पर्यटकों को उनकी बर्थ पर पैंट्री में निर्मित शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस पूर्णतः वातानुकूलित पर्यटक ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और एसी तृतीय श्रेणी के यात्री कोच के अतिरिक्त दो रेल डाइनिंग रेस्तरां, एक आधुनिक किचन कार व यात्रियों के लिए फुट मसाजर, मिनी लाइब्रेरी, आधुनिक एवं स्वच्छ शौचालय और शॉवर क्यूबिकल आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर एवं सीसीटीवी कैमरे भी प्रत्येक कोच में उपलब्ध रहेंगे।

काशी में बज रही है प्रगति की घंटी

"काशी आज केवल पुरातनता ही नहीं, प्रगति का भी प्रतीक है।"

–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सूत्र/रे.स.ब्यू- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अप्रैल को काशी में 3,880 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस प्राचीन शहर को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। सड़कें चौड़ी की जा रही हैंय स्कूलों को उन्नत बनाया जा रहा है और नए बिजलीघर स्थापित किए जा रहे हैं। काशी अपनी जड़ें जीवित रखते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में विकास के तहत कुल 48,459 करोड़ रुपय की लागत से 580 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वाराणसी में आधारभूत ढांचे में सुधार, विरासत को संरक्षित रखना और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है।

काशी की विकास यात्राः उल्लेखनीय उपलब्धियां

- **7 नवंबर, 2014 :** पावरलूम (विद्युत शक्ति से चलने वाला करघा) सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया और जिला सहकारी बैंकों के लिए 2,375 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की गई।
- **18 सितंबर, 2015:** काशी नगरी के उन्नयन के लिए 572 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, साथ ही निकटवर्ती जिलों को जोड़ने वाली सड़कों के लिए 11,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया।
- **22 दिसंबर, 2016:** विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखे जाने सहित 2,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
- **22 सितंबर, 2017:** प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए व्यापार सुविधा केंद्र, दीनदयाल हस्तकला संकुल का लोकार्पण किया।
- **14 जुलाई, 2018:** 900 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।
- **8 मार्च, 2019 :** प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ गलियारे का शिलान्यास किया।
- **30 नवंबर, 2020:** प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा सुगमता के लिए 2,447 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित छह लेन वाले 73 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली रातभर में यात्रा पूरी करने वाली निजी तौर पर संचालित रेल सेवा महाकाल एक्सप्रेस आरंभ की गई।
- **13-14 दिसंबर, 2021:** लगभग 339 करोड़ रुपये के परिव्यय से निर्मित श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रथम चरण का उद्घाटन।
- **7 जुलाई, 2022:** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें वाराणसी स्मार्ट सिटी और 590 करोड़ रुपये लागत की शहरी परियोजनाएं शामिल हैं।
- **13 जनवरी, 2023 :** प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज सेवा 'एमवी गंगा विलास' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- **18 दिसंबर, 2023:** प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया ।
- **10 अक्टूबर, 2024:** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6,100 करोड़ रुपये लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

तीर्थयात्रा से लेकर विशिष्ट अनुभव तक

वाराणसी में पर्यटन यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह इतिहास, आस्था और जीवंत संस्कृति से गुजरने का अनुभव है। निम्नलिखित कुछ पहल द्वारा वाराणसी में पर्यटन को नया आकार दिया जा रहा है:

एमवी गंगा विलासः विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज

13 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज वाराणसी से चलकर 28 फरवरी 2023 को डिब्रूगढ़ में पूर्ण हुआ।

टेंट सिटीः नदी तट पर आरामदायक अनुभव

शहर में गंगा नदी के तट पर स्थापित टेंट सिटी का 13 जनवरी, 2023 को उद्घाटन किया गया। वार्षिक तौर पर अक्टूबर से जून तक संचालित ये टेंट शहर में सैलानियों की बढ़ती संख्या को निवास सुविधा और नदी के किनारे रहने का अनूठा और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं।

श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर

5.5 एकड़ क्षेत्र में फैली 355 करोड़ रुपये की परिवर्तनकारी परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर, 2021 को किया गया। यह गलियारा काशी विश्वनाथ मंदिर को चार लेन मार्ग द्वारा सीधे गंगा नदी से जोड़ता है और मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुगमता प्रदान करता है।

स्मारक प्रकाशमान करने की परियोजनाएं

वाराणसी के ऐतिहासिक स्मारकों की श्यात्मक सुंदरता बढ़ाने के लिए कई प्रकाश परियोजनाएं आरंभ की गई हैंः वर्ष 2015 में, धमेख स्तूप, चौखंडी स्तूप, लालकन का मकबरा और मान महल जैसे स्मारकों को प्रकाशमान करने के लिए 5.12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वर्ष 2017 में, दशाश्वमेध से दरभंगा घाट, तुलसी मानस मंदिर और सारनाथ संग्रहालय को प्रकाशमान करने के लिए 2.93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।

काशी के आधारभूत ढांचे का विकास

काशी के आधारभूत ढांचे के विकास में वर्ष 2021 से 2025 तक व्यापक प्रगति हुई है। 25 अक्टूबर, 2021 को 72.16 किलोमीटर लंबी सड़क वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-20 (पैकेज-दो) का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना में 3,509 करोड़ रुपए की लागत आई। नमो घाट (खिड़किया घाट) का पुनर्विकास कार्य 95.2 करोड़ रुपए के परिव्यय से 15 नवंबर, 2024 को पूर्ण हुआ। घाट अब एक कैफेटेरिया, दृश्य अवलोकन मंच और विरासत भित्ति चित्र से युक्त हैं। राजघाट पर नौकाओं से उत्तर कर बाहर आने के लिए जेटी के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत आई। क्रूज बोट के बेड़े में प्रत्येक वोट की कीमत 20 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, रिवरफ्रंट के साथ पर्यटन क्षेत्र में वॉकवे, दृश्य अवलोकन डेक और फूड कोर्ट है। क्रूज नौकाओं का मार्च, 2023 में परिचालन आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2025 तक फ्लाईओवर, सड़क पुल और एक हवाई अड्डे के अंडरपास के लिए 980 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है।

हथकरघा और हस्तशिल्प निर्माण पुनरुद्धार

वाराणसी अपनी आध्यात्मिक आभा के साथ ही हथकरघा और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है। कारीगरों की कई पीढ़ियों ने अपनी कुशलता से रेशमी वस्त्रों की बुनाई, लकड़ी और पत्थरों पर नक्काशी, धातु की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन और आभूषण निर्माण की कला में महारत हासिल की है। उनकी शिल्प कलाएं और निर्माण अनूठे कौशल और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। इनमें बनारसी साड़ियां , पत्थरों पर महीन जालीदारी का काम , बनारस गुलाबी मीनाकारी और लकड़ी पर लाह लेप युक्त वस्तुएं और बर्तन तथा खिलौने आदि को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिले हैं, जो उनकी प्रामाणिकता और उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। इन पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने और सहायता के लिए सरकार ने 2014-15 के केंद्रीय बजट में एक व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को उनके उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करना है। 300 करोड़ रुपये की कुल लागत से 7.93 एकड़ में बना यह परिसर स्थानीय शिल्पकला वस्तुओं के प्रदर्शन, प्रशिक्षण और बिक्री का प्रमुख स्थल है। इस केंद्र का उद्घाटन 22 सितंबर, 2017 को हुआ था और आज यह वाराणसी की कलात्मक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

काशी में शिक्षा और स्वास्थ्य अभियान

काशी में व्यापक निवेश द्वारा अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में अंतर-विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र (आईयूटीईसी) का उद्घाटन 23 दिसंबर, 2021 को किया गया। 107.36 करोड़ रुपए के परिव्यय से निर्मित इस केंद्र का उद्देश्य 1,000 छात्रों के लिए दो वर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रम कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में बीएचयू में 32.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 3.3 पेटाफ्लॉप पीक प्रदर्शन वाले परम शिवाय सुपरकंप्यूटिंग सेंटर का उद्घाटन किया। कृषि से संबंधित क्षेत्र में, 11 अप्रैल, 2025 को बनास डेयरी दूध आपूर्तिकर्ताओं को 105 करोड़ रुपए का बोनस प्रदान किया गया। विद्युत क्षेत्र में, नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना और ट्रांसमिशन उन्नयन के लिए 1,820 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सिगरा में खेलों के लिए विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में डिजाइन किए गए स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्विकास एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका कुल बजट 180.03 करोड़ रुपए (प्रथम चरण में 90.01 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 90.02 करोड़ रुपए का व्यय) है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्टूबर, 2024 को इसका उद्घाटन किया। काशी आज दीप्तिमान उदाहरण है कि विरासत और आधुनिकता एक साथ फल-फूल सकते हैं। बुनियादी ढांचे, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परियोजनाओं के साथ यह शहर अपने आध्यात्मिक सार को संरक्षित रखते हुए एक जीवंत, भविष्य की पहचान भी स्थापित कर रहा है।

पद्म पुरस्कार–2026 के लिए 31 जुलाई, 2025 तक किए जा सकेंगे नामांकन

सूत्र/रे.स.ब्यू- पद्म पुरस्कार-2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 15 मार्च 2025 से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरर कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें रा ट्रीय पुरर कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 'उत्कृष्ट कार्य' के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं। सरकार पद्म पुरस्कारों को "पीपल्स पद्म" बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं। नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (citation) (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (**https://mha.gov.in**) पर 'पुरस्कार और पदक' शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्कार पोर्टल (**https://padmaawards. gov.in**) पर उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित संविधि (statutes) और नियम वेबसाइट पर **https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx** लिंक पर उपलब्ध हैं।

भारत का 6 जी विजन

सूत्र/रे.स.ब्यू- सरकार ने मार्च 2023 में भारत 6जी विजन दस्तावेज जारी किया है, जिसका उद्देश्य 6जी नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को डिजाइन, विकसित और तैनात करना है जो दुनिया के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जीवन अनुभव के लिए सर्वव्यापी बुद्धिमान और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं ताकि 2030 तक भारत को 6जी तकनीक में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थान दिलाया जा सके। सरकार ने देश में 6जी तकनीक के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- देश में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 6जी टीएचजेड टेस्टबेड और एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्टबेड नामक दो टेस्टबेड को वित्तपोषित करना।
- देश में क्षमता निर्माण और 6जी के लिए तैयार शैक्षणिक और स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों में 100 5जी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई।
- 6जी इको-सिस्टम के लिए अनुसंधान में तेजी लाने के लिए, 6जी प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक रोडमैप के अनुरूप अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 6जी नेटवर्क इको-सिस्टम पर 111 अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
- सरकार ने 'भारत 6जी अलायंस' की स्थापना की सुविधा प्रदान की है, जो भारत 6जी विजन के अनुसार कार्ययोजना विकसित करने के लिए घरेलू उद्योग, शिक्षा, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और मानक संगठनों का गठबंधन है। इसने 6जी वायरलेस प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु वैश्विक सहयोग बढ़ाने हेतु अग्रणी वैश्विक 6जी गठबंधनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने डब्ल्यूटीएसए 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2024 के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय 6जी संगोष्ठी का भी आयोजन किया है। संगोष्ठी का उद्देश्य 6जी प्रौद्योगिकी में स्थानीय और वैश्विक प्रगति का पता लगाना था, तथा उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाना था।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ अंतरराष्ट्रीय मोबाइल प्रौद्योगिकी (आईएमटी) 2030 ढांचे में योगदान दिया है, जिसे उद्योग द्वारा 6जी भी कहा जाता है, जिसमें 6जी के छह उपयोग परिदृश्यों में से एक के रूप में 'सर्वव्यापी कनेक्टिविटी' को शामिल किया गया है और 6जी प्रौद्योगिकी की क्षमताओं के रूप में कवरेज, अंतरसंचालनीयता और स्थायित्व को शामिल किया गया है।

स्टैंड–अप इंडिया के 7 वर्ष–आकांक्षाओं को उपलब्धियों में परिवर्तन

सूत्र/रे.स.ब्यू- 5 अप्रैल 2016 को अपने आरंभ के बाद से, स्टैंड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य पर है। इसका उद्देश्य नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए बैंक लोन प्रदान करके बाधाओं को तोड़ना है। बीते 7 वर्षों में, इस योजना ने न केवल व्यवसायों को वित्त पोषित किया है- इसने सपनों को पोषित किया है, आजीविका का सृजन किया है और पूरे भारत में समावेशी विकास को आगे बढ़ाया है।

स्टैंड–अप इंडिया के अंतर्गत उपलब्धियां

स्टैंड-अप इंडिया योजना ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दिखाई है, जिसकी शुरुआत के बाद से स्वीकृत कुल राशि 31 मार्च 2019 तक 16,085,07 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 मार्च 2025 तक 61,020,41 करोड़ रुपये हो गई। यह एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को दर्शाता है, जो देश भर में उद्यमियों को सशक्त बनाने में योजना के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

इस योजना ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों और महिला उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सशक्तिकरण को प्रतिबिंबित किया (मार्च 2018 से मार्च 2024 तक):

- अनुसूचित जाति के खाते बढ़कर 9,399 से 46,248 हो गए, तथा लोन की राशि बढ़कर 1,826.21 करोड़ रुपये से 9,747.11 करोड़ रुपये हो गई।
- अनुसूचित जनजाति के खाते बढ़कर 2,841 से 15,228 हो गए, तथा स्वीकृत लोन की राशि बढ़कर 574.65 करोड़ रुपये से 3,244.07 करोड़ रुपये हो गई।
- 2018 से 2024 तक, महिला उद्यमियों के खाते बढ़कर 55,644 से 1,90,844 हो गए, तथा स्वीकृत राशि बढ़कर 12,452.37 करोड़ रुपये से 43,984.10 करोड़ रुपये हो गई।

स्टैंड-अप इंडिया योजना एक बदलावकारी पहल रही है, जिसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अपने व्यावसायिक विचारों को हकीकत में बदलने के लिए सशक्त बनाया है। लोन स्वीकृति और वितरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ, यह समावेशी विकास को प्रोत्साहन देना जारी रखता है। यह योजना केवल लोन के बारे में नहीं हैय यह अवसर पैदा करने, बदलाव को प्रेरित करने और आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने के बारे में है।

स्ट्रेच करें, सांस लें, अपडेट रहें: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 न्यूजलेटर लाइव हुआ

सूत्र/रे.स.ब्यू- आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उत्सव की तैयारी के लिए एक समर्पित न्यूजलेटर लॉन्च किया है। यह न्यूजलेटर, जो दुनिया भर के हितधारकों और दर्शकों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा, आयोजन से कुछ ही सप्ताह पहले लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य योग के महत्व और 'एक पृथ्वी, समान स्वास्थ्य के लिए योग' विषय के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने न्यूजलेटर की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह कदम समय पर और पारदर्शी अपडेट सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के 'मन की बात' में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए बताया, जिसमें योग को वैश्विक स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एकत्र किया गया है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा, ''यह न्यूजलेटर योग के प्रति उत्साह बढ़ाएगा और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।'' उन्होंने इस प्रयास को योग और समग्र कल्याण के साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के रूप में प्रस्तुत किया। न्यूजलेटर का मुख्य उद्देश्य आयोजन से संबंधित नवीनतम अपडेट देना है, जिसमें पंजीकरण पोर्टल, भागीदारी के दिशा-निर्देश, और 'हरित योग' जैसे अभियान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न योग संस्थानों, शैक्षिक संगठनों, और सरकारी निकायों के साथ संवाद को सुदृढ़ करेगा, जिससे एक साझा दृष्टिकोण का निर्माण होगा। इस न्यूजलेटर में वैश्विक मिशनों, योग ऐप्स, और डिजिटल अभियानों को उजागर किया जाएगा, जो 'योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ' के वैश्विक संदेश को फैलाने का काम करेंगे। यह संवाद सेतु के रूप में काम करेगा और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में पूर्व-कार्यक्रमों, कर्टन रेजर और अन्य पहलुओं पर नियमित रूप से अपडेट प्रदान करेगा। योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने का यह कदम भारत की भूमिका को वैश्विक कल्याण आंदोलन के नेता के रूप में स्थापित करेगा और दुनिया भर में योग का प्रचार करेगा। अधिक जानकारी और न्यूजलेटर की सदस्यता लेने के लिए : **https://yoga.ayush.gov.in/YAP/IDY-Newsletter/index.php**

'हरित योग' व्यक्तिगत और भूमंडलीय स्वास्थ्य दोनों को पोषित करता है: केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव

सूत्र/रे.स.ब्यू- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की उलटी गिनती की शुरुआत 07 अप्रैल, 2025 को ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर में हुई, जहाँ 6000 से अधिक योग प्रेमियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल (CYP) का अभ्यास किया। इस आयोजन के साथ ही आयुष मंत्रालय के एक विशिष्ट कार्यक्रम 'हरित योग' का भी भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने किया। उन्होंने कहा, ''हरित योग व्यक्तिगत और भूमंडलीय स्वास्थ्य दोनों को पोषित करता है। जिस प्रकार योग शरीर और मन को संतुलन देता है, उसी प्रकार व क्षारोपण पृथ्वी को स्वस्थ बनाता है।'' इस अवसर पर 5000 से अधिक औषधीय पौधों का वितरण किया गया और गणमान्य अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया। 'हरित योग' को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल से जोड़ते हुए, इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण की सामूहिक चेतना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित IDY 2025 की थीम ''एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग'' को साकार करते हुए यह आयोजन योग और सतत विकास के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करता है। ओडिशा की उपमुख्यमंत्री श्रीमती पार्वती परिडा, सांसद डॉ. संबित पात्रा, और आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने आयोजन को गरिमा प्रदान की। डॉ. काशीनाथ समागंडी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की टीम ने CYP का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उपलक्ष्य में इस वर्ष 10 विशिष्ट कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिनमें योग संगम, योग समावेश, योग कनेक्ट, योग महाकुंभ, सम्योगम् और हरित योग प्रमुख हैं। 'हरित योग' कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की उस सोच को मूर्त रूप देता है, जिसमें योग को प्रकृति से जोड़ते हुए जन-जागरूकता और सतत भविष्य के निर्माण की ओर प्रेरित किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने थाईलैंड में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा के लिए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की

सूत्र/रे.स.ब्यू- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल) शिखर सम्मेलन के दौरान पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा, ''जन स्वास्थ्य हमारे सामूहिक सामाजिक विकास का अहम स्तंभ है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत बिम्सटेक देशों में कैंसर देखभाल के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग करेगा। इसके साथ ही, अनुसंधान और पारंपरिक चिकित्सा के प्रसार हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी।''भारत और थाईलैंड दोनों की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। इस साझेदारी से शोध, विकास और शैक्षणिक सहयोग को नया आयाम मिलेगा। पिछले वर्ष भारत के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर और थाईलैंड के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर भी हुए थे। इसके तहत, आयुष मंत्रालय की ओर से आईसीसीआर छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा की पढ़ाई के लिए विदेशी छात्रों को अवसर दिया जा रहा है। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और योग में स्नातक, स्नातकोत्तर व पीएचडी स्तर की पढ़ाई शामिल है। पिछले 5 वर्षों में बिम्सटेक देशों के 175 छात्र इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इस घोषणा से भारत और थाईलैंड के बीच पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग और गहरा होगा और बिम्सटेक क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में अहम योगदान मिलेगा।

पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षो की भाँति आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

सहयोग राशि:

१. उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
२. उच्च अधिकारी- 3500 रु. मात्र
३. अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
४. रेलकर्मी/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

पंजीकृत कार्यालय

502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।

कैंप कार्यालय- अनिल केन (रिपोर्टर) कार्यालय 8439 आर्य नगर पहाड़गंज दिल्ली-55

समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव दि. इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि. 329/255 चक, जीरो रोड इलाहाबाद से मुद्रित एवं 502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।

आर.एन. आई नं. 51097-90

पोस्ट ए.डी.-8

मो. 9773946044 / 9793956044

फोन नं. 0532-2418040

आयुष उत्पादों के निर्यात और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय योजना।

सूत्र/रे.स.ब्यू- आयुष मंत्रालय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत मंत्रालय भारतीय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग और आयुर्वेद जैसी चिकित्सा विधाओं के प्रचार और मान्यता, तथा वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है।

अब तक मंत्रालय ने:

- 24 देश-दर-देश स्तर और
- 51 संस्थान-दर-संस्थान स्तर के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन समझौता ज्ञापनों के तहत वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान, प्रशिक्षण व कार्यशालाएं संचालित की जा रही हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना से शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिल रहा है। योग के प्रचार हेतु 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। अब तक इस दिवस के प्रचार-प्रसार पर लगभग ₹161 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। हर वर्ष इसकी पहुंच और भागीदारी में वृद्धि देखी गई है।

शिक्षा क्षेत्र में योगदान: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के अनुसार योग को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य और कक्षा 11–12 में वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। एनसीईआरटी ने इसके लिए विशेष पाठ्यक्रम और मॉड्यूल तैयार किए हैं। योग प्रमाणन बोर्ड (YCB), आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यरत, योग प्रशिक्षकों को प्रमाणन और संस्थानों को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य योग अभ्यास में गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित करना और योग को एक करियर कौशल के रूप में बढ़ावा देना है।

आयुष मंत्रालय ने गांधीनगर में विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 का आयोजन किया।

सूत्र/रे.स.ब्यू- विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 के अवसर पर, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने गांधीनगर, गुजरात में महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में एक भव्य दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. सैमुएल हैनिमैन की 270वीं जयंती का उत्सव मनाना था, और इसमें विश्वभर से होम्योपैथी के अग्रणी विशेषज्ञ, चिकित्सक, शोधकर्ता, शिक्षाविद और उद्योग के पेशेवर एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था ''होम्योपैथी में शिक्षा, अभ्यास और अनुसंधान'' और इसमें भारत और विदेश से 8,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पैनल चर्चाएँ, प्रदर्शनियाँ, और वैज्ञानिक शोधपत्र प्रस्तुतियाँ हुईं, जो होम्योपैथी को वैश्विक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में और प्रभावी बनाने पर केंद्रित थीं। मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव, स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी उपस्थित थे। आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि ''होम्योपैथी केवल एक विकल्प नहीं है, यह एक विज्ञान है जो करुणा और प्रमाण में निहित है।'' उन्होंने होम्योपैथी में शोध, शिक्षा और सार्वजनिक पहुंच के द्वारा इसके दायरे को और विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। संगोष्ठी के दौरान, महत्वपूर्ण प्रकाशन, सम्मेलन स्मारिका, और होम्योपैथी अभिलेखागार के ई-पोर्टल का विमोचन किया गया। इसके साथ ही औषधि परीक्षण पर एक वृत्तचित्र फिल्म भी रिलीज की गई, जो इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्यों और दस्तावेजीकरण को प्रदर्शित करती है। इस अवसर पर होम्योपैथी उद्योग की अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें शिक्षा और उद्यमिता को जोड़ा गया और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया

सूत्र/रे.स.ब्यू- आयुष मंत्रालय ने आयुष भवन में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के एक सत्र का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के कर्मचारियों के सेवा उन्मुखीकरण और पेशेवर कौशल को बढ़ाना था। यह कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन 18 मार्च को आयुष मंत्रालय के सचिव, वैद्य राजेश कोटेचा द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने संबोधन में उत्तरदायी और कुशल कार्यबल के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कर्मचारियों को सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए अपने दैनिक दायित्वों में प्रशिक्षित दृष्टिकोण को लागू करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में सत्र का संचालन डॉ. सुबोध कुमार द्वारा किया गया, जबकि सुश्री शिप्रा सिंह ने इसे संचालित किया। इस चरण में संवादात्मक प्रारूप अपनाया गया, जिसमें पारंपरिक व्याख्यानों के बजाय व्यावहारिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें चर्चाएँ, टीम अभ्यास, और समस्या-समाधान गतिविधियाँ शामिल थीं, जो कर्मचारियों को उनके दायित्वों और योगदानों पर विचार करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई थीं। कार्यक्रम में आत्म-जागरूकता, प्रेरणा और नेतृत्व जैसे विषयों पर चार सत्र आयोजित किए गए। इसके साथ ही, आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में चल रही पहलों से संबंधित केस स्टडीज को साझा किया गया, जो कर्मचारियों को व्यावहारिक संदर्भ प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ। मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी दिखाई, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों में व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और सार्वजनिक सेवा के व्यापक प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से आयुष मंत्रालय अपने कार्यबल के क्षमता और दक्षता को उन्नत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

लू का प्रकोप –बच्चों को सुरक्षित रखने के प्रभावी तरीके

सूत्र/रे.स.ब्यू- गर्मी का मौसम आते ही हीटवेव का प्रभाव पूरे देश में महसूस होने लगता है। इस अत्यधिक तापमान के कारण बच्चों को खास ध्यान देने की जरूरत होती है, बच्चों के लिए गर्मी की लहर एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, लेकिन कुछ सरल और प्रभावी उपायों से उन्हें इस मौसम में सुरक्षित रख सकते हैं।

हीटवेव के प्रभाव: गर्मी की लहर के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अत्यधिक तापमान और आर्द्रता के कारण निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं:

हीटस्ट्रोक (लू लगना): यह एक गंभीर स्थिति होती है, जब शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। सिरदर्द, उल्टी, चक्कर, और थकान जैसी समस्याएं इसका संकेत हो सकती हैं।

निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन): अत्यधिक गर्मी में शरीर जल्दी पानी खोता है, जिससे बच्चों में निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है। इससे उनकी ऊर्जा में कमी, चिड़चिड़ापन और शारीरिक कमजोरी हो सकती है।

थकान और चक्कर: गर्मी के प्रभाव से बच्चों को अधिक थकान और चक्कर आ सकते हैं, जो उनकी सामान्य गतिविधियों में रुकावट डाल सकते हैं।

बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय:

पानी और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं: बच्चों को हाइड्रेटेड रखना इस मौसम में सबसे अहम हिस्सा है। उन्हें नियमित रूप से पानी पिलाएं, साथ ही ताजे फलों का जूस, नारियल पानी और घर का शरबत जैसे तरल पदार्थ भी दें। यह न केवल उन्हें ठंडक पहुंचाते हैं, बल्कि शरीर के अंदर पानी की कमी को भी पूरा करते हैं।

ठंडी और हवादार जगह पर आराम: बच्चों को हमेशा ठंडी जगह पर आराम करने दें, जहां अच्छी हवा आती हो। ठंडे कमरे में आराम करने से उनका शरीर सही तापमान पर बना रहता है। अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो सुबह के समय या शाम को जब तापमान कम हो, बाहर जाएं।

हल्के और आरामदायक कपड़े पहनाएं: गर्मी में बच्चों को हल्के, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। यह न केवल उन्हें आरामदायक बनाएंगे, बल्कि शरीर को ठंडा भी रखेंगे। हल्के रंग सूरज की गर्मी को अधिक अवशोषित नहीं करते, जिससे शरीर ठंडा रहता है।

ताजे फल और पोषण से भरपूर आहार: गर्मी में बच्चों को ताजे फल जैसे तरबूज, खीरा और खरबूजा देना न केवल उन्हें ठंडक पहुंचाता है, बल्कि हाइड्रेशन भी बनाए रखता है। साथ ही, हल्का और पोषक आहार दें, जिसमें फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा हो।

हीटस्ट्रोक के लक्षण पहचानें: बच्चों में हीटस्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना जरूरी है। अगर बच्चे को अत्यधिक प्यास, तेज बुखार, उल्टी या चक्कर महसूस हो रहे हों, तो उसे तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं और पानी पिलाएं। गंभीर स्थिति में तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें।

धूप से बचाव: बच्चों को सीधी धूप में बहुत देर तक न रखें। यदि बाहर जाना जरूरी हो, तो उन्हें टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन का उपयोग करने की आदत डालें। इससे उनकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाव मिलेगा और वे सुरक्षित रहेंगे। गर्मी मे लू के दौरान बच्चों की देखभाल बेहद अहम है। कुछ सरल उपायों से बच्चों को न केवल गर्मी से बचा सकते हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं।

Shri Arun Kumar Jain, General Manager Holds Detailed Review on Safety of Train Operations

Source/SCR- Shri Arun Kumar Jain, General Manager, South Central Railway held a detailed review meeting on the safety of train operations and further strengthening of the working system on the zone. Shri Neeraj Agrawal, Additional General Manager, SCR participated in the meeting along with all the Principal Heads of Departments. Divisional Railway Managers (DRMs) of all six divisions i.e., Secunderabad, Hyderabad, Vijayawada, Guntakal, Guntur, and Nanded joined the review meeting held through video conference on 07th April, 2025 at Rail Nilayam, Secunderabad. Shri Arun Kumar Jain conducted a detailed review of the safety of train operations across the zone. He instructed the officials and staff to strictly adhere to the safety rules and procedures as per the Railway Board guidelines issued from time to time. He also stressed ensuring safety in train operations and instructed not to follow any shortcut methods. He advised the staff to be more vigilant while on duty to avoid any untoward incidents. Shri Arun Kumar Jain also reviewed the progress of various safety drives being carried out on the zone pertaining to the safety of rail tracks and signaling systems. He also examined the safety action plans of the Mechanical, Engineering, and Signal & Telecommunications departments and reviewed the availability of safety items such as smoke detectors, fire extinguishers, etc. Further, the General Manager held a detailed review on the safety drive carried out at Amrit station worksites across the zone to ensure compliance with all safety procedures and guidelines during construction works. He also instructed the officials to take immediate action on any abnormal situations noticed to avoid unsafe incidents.

WR's MUMBAI CENTRAL DIVISION ACHIEVES HIGHEST EVER COMMERCIAL REVENUE IN 2024-25

Source/WR- Western Railway makes its best possible efforts to increase its revenue and continue to maintain its momentum. For the first time in the history of WR's Mumbai Central Division, the division achieved its highest ever commercial revenue in FY 2024-25. The division achieved almost ₹4485 Cr in commercial revenue and has registered its best ever revenue in many categories. Shri Ashok Kumar Misra, General Manager of Western Railway congratulated the team on achieving this milestone. According to a press release issued by the Chief Public Relations Officer of Western Railway, the commercial performance of WR's Mumbai Central Division has been remarkable, achieving record-breaking revenues, operational efficiencies, and significant digital advancements. The division recorded its best ever revenue figures in Commercial, Passenger, Suburban, Non-Suburban, PRS, AC EMU Passengers & Revenue, Freight, Parking, and Catering categories. The division also saw the highest revenue in the Passenger segment, registering over ₹3782 Cr (Suburban and Non-Suburban), while also registering the best-ever revenue in the PRS segment. The popularity of the AC local trains is also reflected in its numbers. Due to the well-planned services of AC locals, 4.65 crore passengers travelled by AC locals in FY 2024-25, generating a revenue of approx. ₹215 Cr. Continuing in this direction, the division also saw its highest-ever revenue in the Freight category (approx. ₹256 Cr). Mumbai Division also recorded its best-ever revenue from Pay & Park contracts (₹14 Cr), along with its contribution through catering stalls (more than ₹16 Cr). The division has successfully enhanced passenger convenience through digital ticketing, PRS modernization, and improved crowd management strategies. Additionally, infrastructure developments, new freight initiatives, and station upgrades have strengthened the division's position as a leader in railway operations. All the efforts made by the division in various fields have led to sustained growth in revenue.

EASTERN RAILWAY SURPASSES SCRAP SALE TARGET FOR FY 2024-25: GENERATED ₹537 CRORES

Source/ER- Eastern Railway has exceeded its scrap sale target for FY 2024-25, achieving ₹537 crore against the ₹480 crore target set by the Railway Board. This marks a 9.82% growth over the ₹489 crore scrap sale revenue of 2023-24 and reinforces its commitment to the Zero-Scrap Mission and sustainability. The achievement was led by General Manager Shri Milind Deouskar, with efforts from the Additional General Manager and Principal Chief Materials Manager. Multiple e-auctions across Howrah, Sealdah, Asansol, and Malda divisions and scrap depots at Belur, Halisahar, and Jamalpur facilitated the revenue surge. Key contributions included the sale of 3.86 lakh condemned PSC sleepers, 1,032 scrap wagons, 70 obsolete locomotives, and 277 ICF & EMU coaches. Additionally, 30,424 metric tonnes (MT) of rails and fittings and 62,544 MT of workshop-generated scrap significantly boosted earnings. The auction of ferrous, non-ferrous, and non-metallic scrap, along with condemned structures and decommissioned machinery, contributed further. Notably, scrap from Burn Standard, Howrah, alone generated ₹30 crore. This is Eastern Railway's highest-ever scrap sale revenue, marking the first time it surpassed ₹500 crore in a financial year. In 2023-24, it had already exceeded its ₹320 crore target and earned the Sales Management Shield from the Hon'ble Minister of Railways. By leveraging the Indian Railways E-Procurement System (IREPS) portal, Eastern Railway ensures transparency and efficiency in its e-auction process. This achievement underscores its commitment to environmental sustainability, operational efficiency, & revenue maximization from obsolete assets.

Central Railway Achieves Remarkable Financial Performance in 2024-25

Source/CR- Central Railway has demonstrated strong financial discipline and a commitment to infrastructure development in the financial year 2024-25, achieving significant improvements across various key performance indicators.

Financial Highlights

1. Revenue Growth and Cost Efficiency:

- Through efficient operations and strict cost control measures, the increase in revenue expenditure was limited to just 5.18% over the previous year.
- Focused monitoring of capital expenditure (CAPEX) resulted in a 9.84% increase over last year.
- Overall earnings saw a steady rise of 1.83%.

2. *Record Investment in Infrastructure:*

- Continuing its emphasis on infrastructure creation, ₹20,894 crore was invested in CAPEX, marking a 9.84% increase compared to the previous financial year.

3 *Significant spending increases in key sectors:*

- Gauge Conversion: Up 49% from last year.
- Traffic Facilities: Increased by 54%.
- Bridge Works: Witnessed an 86% rise.
- Customer Amenities: A substantial investment of ₹1,250 crore, compared to ₹679 crore in FY 2023-24, reflecting a growth of ₹571 crore.

These achievements underscore Central Railway's commitment to operational efficiency, financial prudence, and passenger-centric infrastructure enhancements. The steady rise in investments and earnings reinforces Central Railway's pivotal role in driving growth and development in the railway sector.

Northern Railway Records Noteworthy Achievement in Train Operations and Passenger Services

Source/NR- Northern Railway registered significant achievements in train operations and passenger services during the financial year 2024-25, enhancing connectivity and capacity. A total of 7 new trains were introduced, including 2 Vande Bharat and 5 Express trains, while 6 trains (4 Express and 2 Passenger trains) were extended to cover more destinations. Additionally, the frequency of 3 trains was increased, providing passengers with more travel options. To accommodate rising demand, the payload capacity of 4 Vande Bharat train sets was increased from 16 coaches to 20 coaches, while 1 set was upgraded from 8 coaches to 16 coaches. Northern Railway also made a significant leap in special train operations, running 13,658 special trains in 2024-25, marking a 204% increase from 4,487 in 2023-24. These included seasonal services catering to peak travel periods such as summer rush, Puja, Holi, and winter rush, with winter rush services increasing by 50.18% and Holi specials by 46.29%. In response to the spiritual travel demands, Northern Railway efficiently operated 2,433 Kumbh Special trains between 01.01. 2025 and 06.03.2025 to Prayag. Additionally, 142 Bharat Gaurav trains were run, promoting cultural and religious tourism. Efforts towards modernization saw 64 new coaches added to 25 train pairs, generating 9,662 additional trips, a 316% rise over the previous year. The railway also upgraded 9 train pairs from ICF (Integral Coach Factory) rakes to LHB (Linke Hofmann Busch) rakes for improved safety and comfort. Furthermore, 37 train pairs were standardized, a 147% increase from last year, and 88 General Class coaches were attached to 41 train pairs, enhancing unreserved travel comfort. These developments highlight Northern Railway's commitment to passenger convenience, modernization, and improved rail operations, ensuring seamless & efficient travel experiences.

World Heritage Day Celebrated at Rail Museum, Kacheguda

Source/SCR- World Heritage Day 2025, observed on April 18th, celebrates the importance of preserving our cultural and natural treasures. On the occasion of World Heritage Day, the Rail Museum at Kacheguda provided free entry to students of schools & colleges, rail passengers, and rail enthusiasts. The Rail Museum exhibits old models of earlier working railway equipment, models, working systems of levers, signal systems, etc. Fans used from 1960 to the present, displayed decade-wise at the exhibition, created more interest among the visitors. A photo displayed of Kacheguda Station's inauguration in the year 1916 by the Nizams drew eye-catching attention from heritage lovers. Kacheguda Railway Station building, built in 1916, has been awarded the Platinum Award by Indian Green Building Council (IGBC) certifications. The Rail Museum offers a glimpse of vintage photographs and exhibits, including those related to the rail network dating back to the Nizam's era. Logos of different railways from the pre-independent era are also showcased in the museum. Exhibits include signaling equipment, prototypes of various locomotives and coaches, tickets, working models, etc. An exclusive seating area is made available to facilitate the screening of audio-visuals related to the history and growth of Indian Railways and other short films on various aspects connected to the railways.

RITES & DP World sign MoU for Logistics Infrastructure Development

Source/RITES- RITES Limited, a premier transport infrastructure consultancy and engineering firm, has signed a transformative Memorandum of Understanding (MoU) with DP World, a global leader in smart end-to-end supply chain logistics, to explore collaborative opportunities in trade, logistics, and infrastructure development. The MoU aims to facilitate mutual cooperation in developing key infrastructure such as ports, multimodal logistics parks, free trade zones, rail connectivity projects, and logistics infrastructure services. The MoU was signed on April 8, 2025, during the 'CEO-Connect: Dubai-India Economic Ties & Opportunities' event in Mumbai. The signing took place in the distinguished presence of HH Sheikh Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Deputy Prime Minister and Minister of Defence of the UAE; Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Government of India; His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayem, Group Chairman and CEO of DP World; and Shri Rahul Mithal, Chairman & Managing Director of RITES Limited, along with other esteemed dignitaries. The partnership aligns with the objectives of the Virtual Trade Corridor (VTC), launched in September 2024 and supported by MAITRI, a digital platform being developed with RITES. The VTC streamlines customs, logistics, and regulatory processes into a unified digital system to enhance trade efficiency between India and the UAE. Strategic workshops since its launch have advanced the development of the VTC proof of concept through key ports including Nhava Sheva, Deendayal, and Jebel Ali. Mr. Rahul Mithal remarked, "This alliance brings together legacy, expertise, and vision to expand 'RITES Videsh' globally." Mr. Sultan Ahmed bin Sulayem added, "This collaboration will create resilient, innovative trade routes and unlock new opportunities for both nations."

IRCON Wins Contract to Transform Rail Signalling in Ajmer Division

Source/RSB- IRCON International Limited has secured a significant order worth ₹127.80 crore from S&T (Construction), North Western Railway, a unit of Indian Railways. The project involves the design, manufacture, supply, installation, testing, and commissioning of a state-of-the-art microprocessor-based Electronic Interlocking (EI) system. The contract, valued precisely at ₹127,80,36,115.49, is to be completed within 24 months from the issuance date of the Letter of Acceptance (LoA). Under the scope of work, IRCON will implement the EI system, featuring an inbuilt block instrument, across 20 stations of the Ajmer Division. The project also encompasses the provision of automatic block signalling and the execution of associated indoor and outdoor works related to signalling & telecommunication systems and equipment. This strategic move will not only enhance operational efficiency but also significantly strengthen the safety and reliability of train movements in the Ajmer Division.

DMRC SIGNS MoU WITH INDIAN RAILWAYS, DMRC WILL PROCURE AUTOMATIC WHEEL PROFILE MEASUREMENT SYSTEMS FOR INDIAN RAILWAYS

Source/DMRC-The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) and the Indian Railways signed a Memorandum of Understanding (MoU) as per which DMRC will procure state-of-the-art 'Automatic Wheel Profile Measurement Systems (AWPMS)' for the Indian Railways. These systems enable the automatic measurement of train wheel profiles and parameters, eliminating human intervention and increasing efficiency and speed. The MoU was signed in the Rail Bhawan on 4th April 2025 by DMRC's General Manager, Business Development Sh. Shiv Om Dwivedi and Sh. Jayant Kumar, Executive Director/ Mechanical Engineering (Modernisation & Development), Railway Board from the Indian Railways. As per the MoU, DMRC shall procure, supply, and install four (04) Automatic Wheel Profile Measurement Systems to Indian Railways. DMRC has already proposed the specifications of the systems and after installation, test and commission them for Indian Railways at the locations specified by them. The AWPMS system was installed for the first time in DMRC at the Mukundpur Depot in July 2023 to facilitate the Automatic Wheel Profile Measurement. The system is designed for non-contact automatic measurement of geometrical parameters of wheelsets. The system uses a combination of laser scanners, stepper motors, RFID tags, and a Server etc. All measurements are performed on a real-time basis. This system eliminates human interface in measurement of the train's wheel profile. The system also automatically transmits an alert message to the user in case of any abnormalities. DMRC will have to provide the systems to Indian Railways at 4 depots within 18 months time. This is an important collaborative step forward for DMRC and Indian Railways as this association would open avenues for many more such ventures where there would be scope for exchange of technology, expertise and mutual skill development.

DFCCIL Partners with IIT-Roorkee for Advanced Rail Safety System

Source/RSB- Taking a major step towards enhancing freight train safety, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL), under the leadership of Managing Director Shri Praveen Kumar, has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with IIT–Roorkee. This collaboration aims to develop a pioneering Broken Rail Detection System, funded by DFCCIL, to strengthen rail safety through early identification of cracks and prevention of rail fractures. The cutting-edge system will utilize thermal cameras to detect fractures in rails and welds, while also monitoring the internal propagation of cracks. This innovative initiative marks a significant move towards building a safer, more reliable freight corridor network in India.

Saving Earth: A Responsibility of Our Generation

The responsibility to protect and preserve the Earth lies heavily on the shoulders of our generation. At a time when environmental challenges are growing rapidly, it is crucial that we adopt sustainable practices in every aspect of life. Reducing, reusing, and recycling materials, conserving precious energy resources, supporting government initiatives focused on environmental protection, and spreading awareness are vital steps. Every small action whether at home, at work, or in our communities contributes to a larger movement towards healing the planet. It is our duty to act today, with determination and compassion, to ensure that future generations inherit a greener, healthier, and more vibrant Earth.

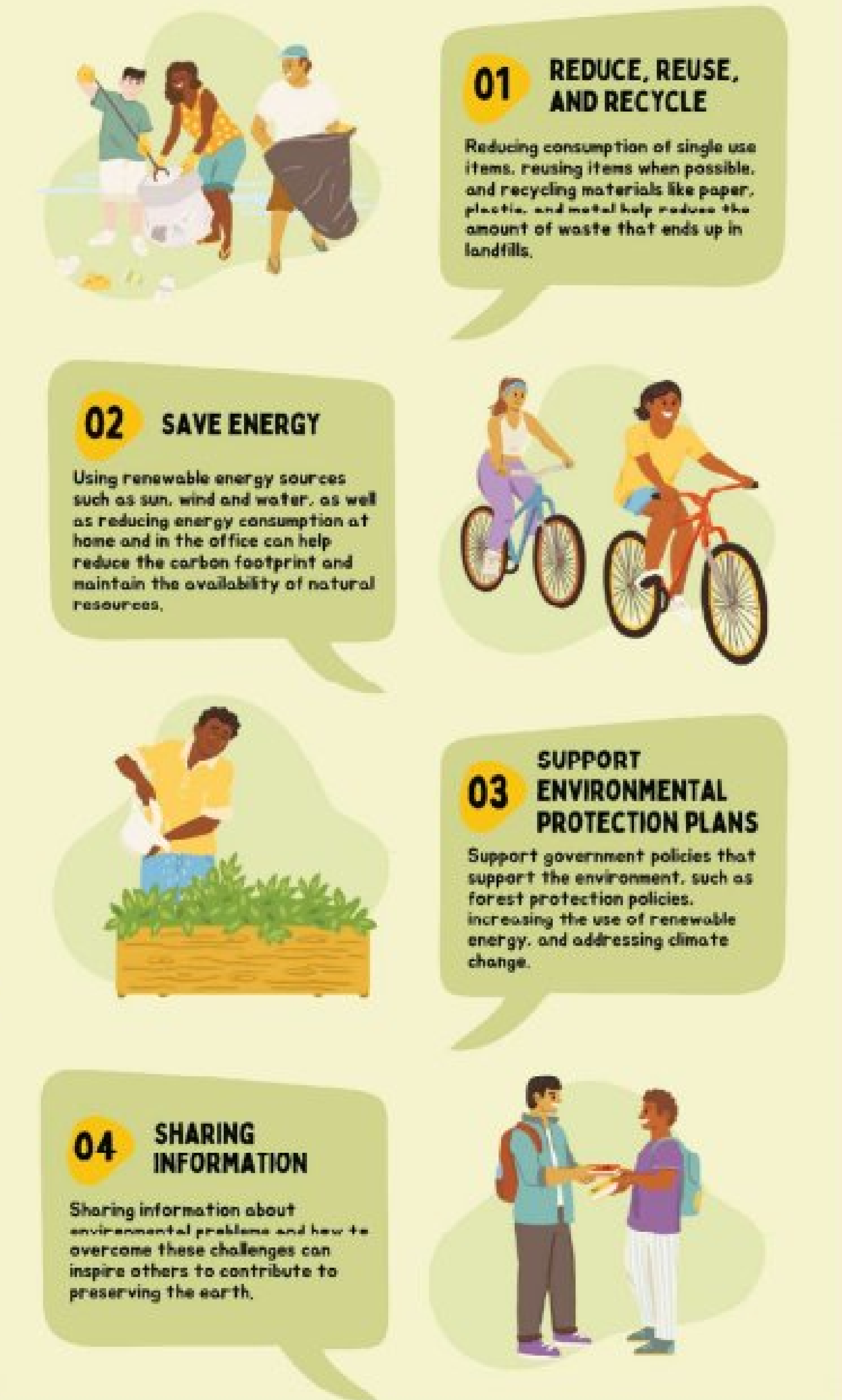

RailTel and NBCC Join Hands for Data Centre Projects

Source/RSB- RailTel Corporation of India Ltd., under the Ministry of Railways, has signed an MoU with NBCC (India) Ltd., under the Ministry of Housing and Urban Affairs, for collaboration in developing Data Centre projects in India and overseas. As per the MoU, RailTel will manage planning, design, installation, and maintenance of IT infrastructure, while NBCC will handle construction, project management, cost control, and quality assurance. Both entities will combine their strengths to deliver complete solutions from concept to commissioning. The collaboration also aims to develop IT and IT-enabled service infrastructure in international markets like Vietnam, Mauritius, UAE, and African countries, with each project governed by separate agreements. The MoU was signed in the presence of CMDs of RailTel, NBCC, and NHPC, along with officials from NIXI and Delhi Police.